CC MM YY KK

RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. बुधवार, 13 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 167 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु. | संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

उदयगिरि और हिमगिरि को नौसेना में शामिल होगी

नई दिल्ली – भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को दो अत्याधुनिक फ्रंटलाइन फ्रिगेट, उदयगिरि (एफ35) और हिमगिरि (एफ34) को एक साथ नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ऐसा पहली बार होगा, जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों के, दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों को, एक ही समय में विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह आयोजन भारत के तेजी से होते नौसैनिक आधुनिकीकरण और कई शिपयार्डों से परिष्कृत युद्धपोतों की आपूर्ति करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की कामयाबी को दर्शाती है। प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज, उदयगिरि, मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा बनाया गया है, जबकि हिमगिरि, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे पी17ए जहाजों में से पहला है। भारतीय नौसेना के लिए एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर, उदयगिरि नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज है। उदयगिरि और हिमगिरि पहले के डिज़ाइनों की तुलना में एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव दर्शाते हैं। करीब 6,700 टन विस्थापन वाले पी17ए फ्रिगेट, अपने पूर्ववर्ती शिवालिक-श्रेणी के फ्रिगेट से करीब पाँच प्रतिशत बड़े हैं और फिर भी इनका आकार अधिक सुडौल है, और इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम है। ये संयुक्त डीजल या गैस (सीओडीओजी) प्रणोदन संयंत्रों द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें डीजल इंजन और गैस टर्बाइन लगे होते हैं, जो कंट्रोलेबल-पिच प्रोपेलर चलाते हैं और एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) के ज़रिए प्रबंधित होते हैं। हथियारों के इस समूह में सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 76 मिमी एमआर गन और 30 मिमी और 12.7 मिमी क्लोज-इन वेपन संयोजन सिस्टम और एंटी-सबमरीन/अंडरवाटर वेपन सिस्टम शामिल है। दोनों जहाज 200 से ज़्यादा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का परिणाम हैं, जो करीब 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करते हैं। उदयगिरि और हिमगिरि का जलावतरण, जहाज़ों के डिज़ाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसके बाद अन्य स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म, जैसे विध्वंसक आईएनएस सूरत, फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरि, पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर, एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, और डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का भी 2025 में ही जलावतरण होना है।

स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कार्यक्रम सुबह 9.05 बजे

मुंबई – भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। राज्य का मुख्य सरकारी कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मंत्रालय, मुंबई में और राज्यपाल द्वारा पुणे में ध्वजारोहण करके मनाया जाएगा। जिला/विभाग मुख्यालयों पर ध्वजारोहण का मुख्य सरकारी समारोह पूरे राज्य में एक ही समय पर, यानी सुबह 9.05 बजे आयोजित किया जाना चाहिए। इस दिन सुबह 8.35 से 9.35 बजे के बीच कोई अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी समारोह आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई कार्यालय या संगठन अपना ध्वजारोहण समारोह आयोजित करना चाहता है, तो उसे सुबह 8.35 से पहले या 9.35 के बाद आयोजित किया जाना चाहिए, शाही प्रोटोकॉल विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी संभागीय/जिला/उप-जिला/तालुका मुख्यालयों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, अमरावती और कोंकण के संभागीय आयुक्त अपने-अपने संभागों और जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित करने के लिए उचित व्यवस्था करें। चूँकि कुछ मंत्री एक से अधिक जिलों के पालक मंत्री हैं, इसलिए सरकार राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए उनके लिए एक जिले की पहचान कर रही है। तदनुसार, उनके द्वारा उस जिले के मुख्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी और राष्ट्रगान बजाया जाएगा और उसके तुरंत बाद, सतर्क स्थिति में आने के बाद राज्य गान बजाया जाएगा। इस अवसर पर भाषणों का विषय स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालना और उपस्थित लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करना होना चाहिए। संबंधित उप-मंडल अधिकारी और तहसीलदार क्रमशः उप-मंडल मुख्यालय और तालुका मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे, तथा सरपंच या ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे।

'गरुड़ दृष्टि' एआई टूल्स के प्रस्तुति में बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

साइबर अपराध पर अंकुश लगाने महाराष्ट्र के पास सबसे अच्छी प्रणाली और तकनीक

नागपुर – सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक द्वेष भड़काने के कारण दंगे भड़कते हुए हम सबसे पहले देखते हैं। महाराष्ट्र के पास अब ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था और तकनीक मौजूद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'गरुड़ दृष्टि' उपकरण ऐसे लोगों को पकड़ने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वे पुलिस भवन में नागपुर पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न साइबर वित्तीय अपराधों की जाँच से प्राप्त 10 करोड़ रुपये के वितरण और 'गरुड़ दृष्टि' सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस परियोजना पर एक प्रस्तुतिकरण में बोल रहे थे। उन्होंने यह राशि धोखाधड़ी के शिकार लोगों को वितरित की। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंघल, संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सर्वश्री वसंत परदेशी, राजेंद्र दाभाड़े, शिवाजी राठौड़ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। हालाँकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने विचारों को व्यक्त करने के एक मंच के रूप में करना अच्छा है, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इस मंच का इस्तेमाल नफ़रत फैलाने, धमकियाँ देने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, झूठी खबरें फैलाने और नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर वित्तीय धोखाधड़ी वाले ये प्लेटफ़ॉर्म विदेशी ऑपरेटरों द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए, सभी को सावधान रहना चाहिए। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके मोबाइल फ़ोन पर आने वाले किसी भी तरह के ऑफ़र वित्तीय धोखाधड़ी का जाल हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई है, तो वे जल्द से जल्द 1930 और 1945 नंबरों पर संपर्क करें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से अपील की। सोशल मीडिया के ज़रिए धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए 'गरुड़ दृष्टि' प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के ज़रिए इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना और उन पर नज़र रखना संभव होगा। अंदर के पेज पर....

'हमारा मंत्रालय' के विशेष अंक का प्रकाशन

मुंबई – सरकार, समाज और व्यक्ति के बीच संवाद को मजबूत करने तथा पाठकों तक विचारोत्तेजक और सूचनाप्रद लेखन पहुंचाने के लिए तैयार की गई गृह पत्रिका 'आपलम मंत्रालय' का विशेषांक मराठी भाषा विभाग की सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी द्वारा प्रकाशित किया गया। विमोचन समारोह में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अजय भोसले, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के निदेशक हेमराज बागुल तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। विशेषांक में 'भारत में प्राचीन रंगों का इतिहास', 'स्कूल शिक्षा विभाग और माननीय न्यायालय के अंतर्संबंध' जैसे गहन और ज्ञानवर्धक लेख शामिल हैं। इस अंक में सरकार के कामकाज के संवेदनशील और मानवीय पहलू को पाठकों तक पहुँचाने और सकारात्मक संचार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। डॉ. कुलकर्णी ने विश्वास व्यक्त किया कि 'आपलम मंत्रालय' पहल पाठकों, समाज और सरकार के बीच संवाद को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाएगी। यह विशेष अंक इस लिंक https://publuu.com/flip-book/945595/2075357 पर निःशुल्क पढ़ने के लिए उपलब्ध है ।

स्व. गोपीनाथराव मुंडे के सपने को साकार करेंगे

नागपुर – जिला सामान्य अस्पताल, नगर विस्तार जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी। दिवंगत लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे एक ऊर्जावान और संघर्षशील नेता थे। एक कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक का उनका सफ़र संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने मराठवाड़ा को सूखा मुक्त बनाने का सपना देखा था। उनके इस सपने को साकार करने के लिए, मराठवाड़ा के हक़ का पानी इस क्षेत्र तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कृष्णा घाटी से 7 टीएमसी पानी मराठवाड़ा लाने की मंज़ूरी मिल चुकी है और इसका काम अंतिम चरण में है। अब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गोदावरी घाटी से 54 टीएमसी पानी मराठवाड़ा लाया जाएगा। उन्होंने लातूर शहर विस्तारित जलापूर्ति योजना और ज़िला सामान्य अस्पताल के काम को मंज़ूरी देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री लातूर में दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का अनावरण करने के लिए दयानंद कॉलेज के मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बोल रहे थे। लोक निर्माण मंत्री और संरक्षक मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल, विधायक सर्वश्री विक्रम काले, संभाजी पाटिल-निलंगेकर, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, अभिमन्यु पवार, रमेश कराड, संजय केनेकर, पूर्व राज्य मंत्री बसवराज पाटिल, पूर्व विधायक शिवाजी पाटिल कावेकर, पूर्व विधायक गोविंद केंद्र, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्र, पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप, जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर-घुगे, पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, नगर निगम आयुक्त श्रीमती। मानसी उपस्थित थे। दिवंगत जननेता गोपीनाथराव मुंडे की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त करना अपना सौभाग्य बताते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख और स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे की मित्रता सर्वविदित थी। आज जिला परिषद परिसर में स्वर्गीय मुंडे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अंदर के पेज पर....

शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित और सुगम पूरी पर दी बधाई

नई दिल्ली – भारतीय संस्कृति की अटूट परंपरा और आस्था की प्रतीक श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में इस वर्ष 4.14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये। इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने में आप सभी का योगदान सराहनीय व अद्वितीय रहा। बाबा बर्फानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में योगदान देने के लिए सभी सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई दी है। श्री अमित शाह ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा "ॐ नमः शिवाय! भारतीय संस्कृति की अटूट परंपरा और आस्था की प्रतीक श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में इस वर्ष 4.14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये। इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में अपना योगदान देने के लिए मैं सभी सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई देता हूँ। इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने में आप सभी का योगदान सराहनीय व अद्वितीय रहा।बाबा बर्फानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें"।

यूके और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मिला प्रवेश

नागपुर – 12 अल्पसंख्यक समुदाय के नवबौद्ध छात्रों के लिए अब विदेश में उच्च शिक्षा का रास्ता साफ हो गया है। सभी छात्रों की विदेशी छात्रवृत्ति आखिरकार मंजूर हो गई है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के विशेष हस्तक्षेप और प्रयासों से 52 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

विदेश जाने वाले छात्रों में सुमित जांभुलकर, निनाद जांभुलकर, कौशिक खोब्रागड़े, प्रिंशु ढोणे, वरुण रामटेके, अभिजीत लोखंडे, पलक ढोणे, सुकेशिनी जीवने, शर्वरी मेश्राम, इशिका इलमे, नितेश वानखेड़े और यश का समावेश है। इन सभी को यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में प्रवेश मिला है, जहां वे साइबर सिक्योरिटी, एमबीए, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मास्टर ऑफ कॉमर्स और डेटा साइंस जैसे कोर्स करेंगे। सभी छात्रों ने "विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना" के तहत आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों और प्रशासनिक अड़चनों के चलते प्रक्रिया अटक गई थी। छात्रों ने मुंबई और पुणे के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर लगाए, फिर भी काम आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार, छात्रों ने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) श्री प्यारे खान से मदद मांगी। श्री खान के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और अथक प्रयासों के बाद ही यह छात्रवृत्ति मंजूर हुई।

छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बाद सभी छात्रों ने प्यारे खान से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री खान ने छात्रों का सत्कार करते हुए विदेश में पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा, "तैरना सीखना है तो डूबने का डर निकालना होगा। सफलता का असली सूत्र है पहला कदम बढ़ाओ, फिर सोचो।" साथ ही, उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद देश लौटकर समाज और राष्ट्र की सेवा करें। इस मौके पर श्री खान ने आगे यह भी कहा, "मैं छात्रों से अपील करता हूं कि वे विदेश में उच्च शिक्षा लेना चाहने वाले छात्रों के लिए जागरूकता फैलाएं और एक मानक कार्यप्रणाली तैयार करें, ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को उच्च शिक्षा की राह में अनावश्यक देरी या बाधाओं का सामना न करना पड़े।"

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए "विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना" संचालित करती है। इस योजना के तहत दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार ने छात्र स्कूल वैन को दी मंजूरी - परिवहन मंत्री

मुंबई – राज्य सरकार ने राज्य के उन अभिभावकों को राहत देने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं जो स्कूल बसों का बढ़ा हुआ मासिक किराया वहन नहीं कर पाने के कारण अपने बच्चों को लाने-ले जाने के लिए अनधिकृत रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। परिवहन विभाग स्कूली छात्रों के सुरक्षित परिवहन और रोज़गार के अवसरों के लिए स्कूल वैन लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

मंत्री सरनाईक ने कहा, "छात्रों का सुरक्षित परिवहन पहली प्राथमिकता है। सुरक्षित परिवहन के साथ-साथ बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल वैन को मंजूरी दी जा रही है।" नए स्कूल वैन से छात्रों के परिवहन का व्यवसाय शुरू करने वालों को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाएँगे। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो राज्य में अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस स्कूल वैन चलाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा अभिभावकों और बस संघों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में, अनधिकृत वाहनों में छात्रों के परिवहन का मुद्दा उठाया गया। देश में सुरक्षित छात्र परिवहन के लिए, केंद्र सरकार ने स्कूल बस विनियम

(ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी AIS-063) के आधार पर, स्कूल वैन विनियम (AIS-204) नामक अद्यतन मानक तैयार किए हैं। छात्रों के परिवहन के लिए 12+1 सीटों वाले चार पहिया वाहनों को स्कूल वैन का दर्जा दिया जाएगा। ये वाहन BS-VI श्रेणी के होंगे। इसमें आधुनिक सुरक्षा तकनीकें जैसे चालक पहचान पत्र, आपातकालीन निकास, वाहन प्रवेश, सीट डिज़ाइन की स्पष्टता के साथ भंडारण रैक, फायर अलार्म सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग शामिल हैं, मंत्री सरनाईक ने बताया। राज्य सरकार 2018 तक परिवहन विभाग के माध्यम से स्कूल वैन के लिए लाइसेंस जारी कर रही थी। हालाँकि, कुछ लोगों ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल वैन छात्रों के परिवहन के लिए असुरक्षित हैं। केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार, राज्य सरकार ने वैन संचालन के संबंध में नियम तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्री सरनाईक ने बताया कि इसी के आधार पर राज्य सरकार ने यह रणनीतिक कदम उठाया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। जो अभिभावक स्कूल बस का किराया नहीं दे सकते, वे छात्रों को लाने-ले जाने के लिए अवैध रिक्शा का सहारा लेते हैं। रिक्शा की तुलना में, वैन ज़्यादा सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करती हैं। वैन के दरवाज़े लॉक होते हैं। चूँकि वाहन चार पहियों वाला होता है, इसलिए उसके पलटने की संभावना नगण्य होती है। वैन में स्कूल बैग, पानी की बोतलें और अन्य सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह होती है।

स्कूल वैन की विशेषताएँ

GPS, डैशबोर्ड पर सीसीटीवी और स्क्रीन, अग्नि अलार्म प्रणाली, यदि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो अलार्म सिस्टम, 40 किमी/घंटा की गति सीमा वाला स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, आपातकालीन दरवाजे, छोटे छात्रों के लिए स्कूल वैन में प्रवेश हेतु सीढ़ियाँ, कार की छत पर स्कूल का नाम।

CC MM YY KK

संपादक की कलम से

विमान हुआ धुआं-धुआं

एम्स्टर्डम जा रहे एक प्लेन के अंदर पावर बैंक में आग लग गई। पावर बैंक में आग लगने के बाद विमान के केबिन में धुआं भर गया। इस घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर प्लेन में सवार एक यात्री ने इसे अपने जीवन की सबसे तनावपूर्ण यात्राओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि धुआं इतना ज्यादा था कि तकिए से उन्हें अपनी नाक को ढकना पड़ा। हालाकि, घटना के बाद विमान सुरक्षित रूप से एम्स्टर्डम में उतर गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। एयरलाइन ने बयान में कहा, 'पावर बैंक के जलने के कारण विमान के केबिन में धुआं भर गया। चालक दल ने निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तुरंत जरूरी कदम उठाए।'' एयरलाइन ने कहा, 'व्यापक सुरक्षा समीक्षा के बाद, विमान में पावर बैंक के इस्तेमाल के जोखिम को कम करने के लिए सख्त रुख अपना रही है।

मिलिंद दहिवले
संपादक

जंगली सब्जियों का स्वाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत - कृषि राज्य मंत्री जायसवाल

नागपुर - प्रकृति ने हमें जंगली सब्जियां प्रदान की हैं जो पश्चिमी फास्ट फूड की तुलना में अलग स्वाद वाली और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और औषधीय जंगली सब्जियां श्रावण के महीने में हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कृषि राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल ने नागरिकों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और फास्ट फूड का सेवन करने वाली युवा पीढ़ी तक पारंपरिक जंगली सब्जियों के स्वाद और स्वास्थ्य मूल्य को फैलाने की अपील की। वह जिला स्तरीय जंगली सब्जी महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। रामनगर मैदान में आयोजित इस जंगली सब्जी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, नागपुर विभाग के कृषि संयुक्त निदेशक उमेश घाटगे, आत्मा की परियोजना निदेशक डॉ. अर्चना कडू, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र मनोहरे और अन्य उपस्थित थे। रामनगर में जिला स्तरीय जंगली सब्जी महोत्सव का शुभारंभ; उपभोक्ताओं के लिए जंगली सब्जियां खरीदने का अनूठा अवसर। हमारे आस-पास स्वास्थ्यवर्धक अनेक वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन जंगली सब्जियों का ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुँचना चाहिए। युवाओं के मन में पुराने स्वाद और नई पीढ़ी के बीच संबंध बनाना चाहिए, ऐसा कृषि राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल ने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि महिला स्वयं सहायता समूह इस बारे में अधिक जागरूक होकर पहल करें, तो उन्हें उमेद के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों और उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जिले में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए उमेद मॉल की स्थापना कर रहे हैं। आत्मा की परियोजना निदेशक डॉ. अर्चना कडू ने बताया कि यह दो दिवसीय जंगली सब्जी महोत्सव कल, 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कृषि विभाग ने इस जिला स्तरीय जंगली सब्जी महोत्सव में बड़ी संख्या में आने की अपील की है।

स्व. गोपीनाथराव मुंडे के सपने को साकार करेंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पेज 1 से आगे....

एक विपक्षी नेता कैसा होना चाहिए, इसका एक अच्छा उदाहरण स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे हैं। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने गृह विभाग संभाला, उनके कार्यकाल में मकोका कानून लाया गया। उन्होंने महाराष्ट्र को अपराध के आतंक से मुक्त कराने के लिए काम किया, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ने हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों पर अडिग रहने की शिक्षा दी। उन्होंने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम विस्तार के लिए आंदोलन किया था। स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे पूरे समाज के लिए अधिकारों के वाहक थे। उनकी शिक्षाओं को अपनाया जाना चाहिए। उन्हें केंद्र में थोड़े समय के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने अपने काम की प्रतिभा दिखाई। अगर उन्हें लंबा कार्यकाल दिया जाता, तो तस्वीर कुछ और होती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

लातूर में रेलवे बोगी निर्माण कारखाना जल्द ही शुरू हो रहा है और इससे निकट भविष्य में 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दिए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कारखाने के लिए आवश्यक कुशल मानव संसाधन जिले में ही तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में राज्य की सभी कृषि भूमि को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ने आम आदमी और मजदूरों को न्याय दिलाया। विधायिका में मुद्दे उठाने का उनका तरीका प्रशंसनीय था। इस अवसर पर पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने कहा। स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे का जीवन संघर्षों से भरा था, उनकी शिक्षा थी कि चाहे कितने भी संकट आ जाएँ, आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुपालन मंत्री पंकज मुंडे ने कहा कि हम उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा, "हम दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे के संघर्ष और कार्यों के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 30 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराने का काम मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में किया जा रहा है।"

मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक टेलीविजन समारोह के माध्यम से जलकोट तालुका के गुट्टी में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत स्थापित पाँच मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना दिन में 772 कृषि पंपों को बिजली प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई 'लातूर जिला: प्रगति की ओर' नामक एक विशेष पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 'उम्मीद' के अंतर्गत तैयार 'हिरकणी हाट' लोगो का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला परिषद की व्हाट्सएप चैटबॉट पहल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 'उम्मीद' के अंतर्गत तुलजाई उद्योग समूह को 2 करोड़ 5 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया और रमाई घरकुल के लाभार्थियों को घरों की चाबियाँ प्रदान की गईं। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र गीता से हुई। उपस्थित गणमान्यों का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पूर्ण-लंबाई वाली प्रतिमा की प्रतिकृति भेंट करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन उद्धव फड़ ने किया। पूर्व राज्य मंत्री बसवराज पाटिल ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया।

आलिया ने मनाया शादी के तीन साल पूरे होने का जश्न

बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी को तीन साल पूरे हो गए हैं। आलिया ने रणबीर को सालगिरह की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर की है। 'रॉकस्टार' अभिनेता द्वारा ली गई इस सेल्फी में रणबीर का चेहरा आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, जबकि इस तस्वीर में आलिया अपने पति के बगल में आराम करती नजर आ रही हैं।

आलिया ने इस प्यार भरी तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, होम, ऑलवेज, हैप्पी 3। इस तस्वीर पर आलिया की सास नीतू कपूर ने रिएक्ट किया और कमेंट में रेड हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया। रणबीर की बहन करीना कपूर खान ने कमेंट सेक्शन में द बेस्ट पीप्स लिखा। साथ में दो रेड हार्ट वाले इमोजी भी बनाए। इस खास दिन पर इस जोड़े को बधाई देते हुए रिया कपूर ने लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी।

आलिया और रणबीर के इस खास मौके के अवसर पर उनकी प्रेम कहानी पर एक नजर डालते हैं। यह जानना रोमांचक हो सकता है कि रणबीर आलिया के बचपन के क्रश थे। आलिया ने खुलासा किया था कि वह संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए ऑडिशन दे रही थीं, जहां रणबीर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। आलिया ने बताया कि वह तुरंत उनसे प्यार कर बैठीं। कई साल बाद आलिया ने करण जौहर के लोकप्रिय टॉक शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में रणबीर से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी।

शेखर कपूर ने सुनाया बचपन का किस्सा

फिल्म निर्माता-निर्देशक शेखर कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने बचपन की यादों को ताजा किया। उन्होंने उन दिनों को याद किया, जब दिल्ली प्रदूषण से मुक्त थी और रात के समय आसमान में तारे चमकते थे और ताजी हवाएं चलती थीं। खुली आसमान की एक तस्वीर के साथ शेखर कपूर ने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा, एक समय था जब दिल्ली प्रदूषित शहर में नहीं आती थी। गर्मियों में हम अपने एक मंजिला घर की छत पर खुले आसमान के नीचे सोते थे। तारे इतने चमकीले थे कि खूब रोशनी लगती थी। मैं लगभग नो साल का था और तारों को उत्सुकता के साथ देखता रहता था। तारों और आकाशगंगा को लेकर मैं अपनी मां से पूछता था- अंतरिक्ष कितनी दूर है? वह कहतीं - बहुत दूर।

शेखर कपूर ने कहा, मैं उस उम्र में था जब शिक्षा का असर मेरे दिमाग पर होना शुरू हो चुका था। मुझे सिखाया गया था कि कुछ भी होने के लिए उसे मापने योग्य होना चाहिए। उसे परिभाषित किया जाना चाहिए। दूरी, लंबाई, चौड़ाई, वजन, और समय से परिभाषित किया जाना चाहिए। नौ साल की उम्र में मैं रात में जागता रहता था और कल्पनाओं में खो जाता था। मैं हमेशा उस आकाशगंगा के बारे में सोचता रहता और छूने की कोशिश करता। उन्होंने कहा, बेशक यह भावनात्मक उथल-पुथल थी।

मैं वहीं लेटा रहता। सो नहीं पाता। निराशा और पीड़ा के आंसू बहते रहते थे और तभी मुझे जादुई औषधि का पता चला। कहानियों का जादू और फिर हर रात मैं इसे एक कहानी में बदल देता था। एक अलग कहानी में। खुद की तलाश जारी रखें। शेखर कपूर प्रकृति प्रेमी हैं। एक अन्य पोस्ट में वह हिमालय की खूबसूरती में डूबे नजर आए थे।

सलमान खान ने जिम में बहाया पसीना

सलमान खान फिर से फिटनेस मोड में आ गए हैं। 59 साल की उम्र में पेड़ पर आसानी से चढ़कर सबको प्रभावित करने के बाद, उन्होंने अपने हालिया वर्कआउट सेशन की कुछ चौंका देने वाली फोटो फैंस के साथ शेयर की हैं। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो फोटो पोस्ट की, जिसमें जिम में पसीना बहाते हुए अपने बड़े बाइसेप्स को दिखाया गया है। प्रेरणा के लिए नेटिज़न्स का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, प्रेरणा के लिए शुक्रिया। रणवीर सिंह ने पोस्ट पर हार्ड हार्ड के साथ प्रतिक्रिया दी। वरुण धवन ने कमेंट सेक्शन में कई फायर इमोजी बनाए।

'ज्वेल थीफ' में काम कर खुश है निकिता

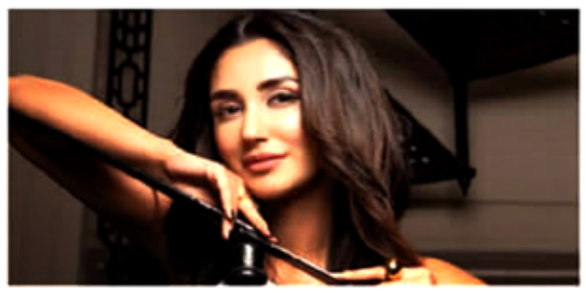

अभिनेत्री निकिता दत्ता फिल्म ज्वेल थीफ में काम कर बेहद खुश है। 'ज्वेल थीफ' : द हीस्ट बिगिन्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस दौरान निकिता दत्ता ने इस फिल्म में अपने किरदार को लेकर उत्साह और अनुभव साझा किए। इस फिल्म का निर्माण सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद ने किया है, जबकि निर्देशक रॉबी ग्रेवाल एवं कूकी गुलाटी हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान, जयदीप अहलावत और कुणाल कपूर भी अहम किरदारों में नजर आयेंगे। निकिता ने बताया ,मैं सिद्धार्थ आनंद की दुनिया का हिस्सा बनी हूं, और मुझे लगता है कि एक अभिनेत्री के तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। सच कहूं तो, मैंने कभी क्लासिक बॉलीवुड हीरोइन वाला टेग महसूस नहीं किया था। लेकिन मुझे यह मौका मिला कि मैं एक क्लासिक बॉलीवुड हीरोइन का किरदार निभा सकूं।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर पीएम मोदी के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शीघ्र शांति बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ और सतत् रुख की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस मामले में हर मुमकिन मदद करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, नोटिस जारी

अमेरिका – बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बारे में प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके उपनाम, मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि वह मजीद ब्रिगेड को बीएलए के विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के डेजिग्नेशन में एक उपनाम के रूप में जोड़ रहा है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है। अक्सर वह पाकिस्तानी सेना को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती रहती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कई आतंकी हमलों के बाद साल 2019 में विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। साल 2019 के बाद से ही बीएलए ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। इनमें मजीद ब्रिगेड के भी हमले शामिल हैं। बीएलए ने 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमले करने का दावा किया। बीएलए ने 2025 में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की जिम्मेदारी ली, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए और 300 से ज्यादा ट्रेन यात्रियों को बंधक बना लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर की गई ये कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संगठन को आतंकवादी घोषित करना आतंक के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। विदेश विभाग ने कहा है कि आज की कार्रवाई संशोधित आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और संशोधित कार्यकारी आदेश 13224 के तहत की गई है। बता दें कि पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कुछ ही समय में दूसरी बार अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की है। वाशिंगटन के दौरे के दौरान असीम मुनीर ने अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की है। मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) कमांडर जनरल माइकल ई.कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के अवसर पर आयोजित कमान परिवर्तन समारोह में भाग लिया।

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदवासी क्षेत्रों में होमस्टे

नई दिल्ली – जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास' के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए टेम्पलेट के साथ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करना है। ये दिशा-निर्देश होमस्टे मालिकों के तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

31 करोड़ असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत

नई दिल्ली – श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है। 5 अगस्त 2025 तक, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक लाभ और पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले से ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया है। (एमजीएनआरईजीएस), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट लॉन्च कीं ताकि उन्हें अपनी समर्पित ई-श्रम माइक्रोसाइट के साथ सशक्त बनाया जा सके और उनकी विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। ये माइक्रोसाइटें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ई-श्रम सेवाओं को तैयार करने, श्रमिक पंजीकरण, डेटा अद्यतन, सत्यापन को सरल बनाने और राज्य-विशिष्ट विश्लेषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

मंत्रालय ने ई-श्रम पर प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को शामिल करने के लिए 12 दिसंबर 2024 को प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह पहल इन एग्रीगेटर्स को ई-श्रम इकोसिस्टम में एकीकृत करती है, प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स की औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे समावेशी और न्यायसंगत श्रम कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। अब तक प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर मॉड्यूल पर 12 प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को शामिल किया जा चुका है, जिनमें ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी, उबर, ओला, अमेज़न, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो, ईकॉम एक्सप्रेस और अंकल डिलीवरी शामिल हैं।

भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में वृद्धि

नई दिल्ली – महामारी के बाद वैश्विक पर्यटन में आई तेज़ी और एक विविध एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गंतव्य के रूप में भारत में बढ़ते विश्वास के कारण मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में वृद्धि हुई है। बेहतर हवाई संपर्क ने प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुँच में सुधार किया है, जबकि पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसके अतिरिक्त, लक्षित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियानों ने भारत की वैश्विक अपील को मज़बूत किया है, जिससे यह दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक उपाय/पहल की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न अभियानों और आयोजनों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देता है। इनमें से कुछ पहलों में "देखो अपना देश" अभियान, "अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट", "भारत पर्व" आदि शामिल हैं। अन्य विशिष्ट विषयों के साथ-साथ विषयगत पर्यटन जैसे कल्याण पर्यटन, पाक-कला पर्यटन, ग्रामीण, पारिस्थितिकी पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि पर्यटन का दायरा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके।

नेरुल में विश्व स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 13 अगस्त को

मुंबई – अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा आयोजित 'विश्व स्कूल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' (अंडर-15 लड़के और लड़कियां) 4 से 13 दिसंबर 2025 तक चीन के शांग्लुओ में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य स्तरीय चयन हेतु मुंबई क्षेत्रीय चयन परीक्षा 13 अगस्त 2025 को सुबह 9.30 बजे नेरुल जिमखाना, नेरुल, नवी मुंबई में आयोजित की जाएगी, यह जानकारी खेल और युवा सेवा उपनिदेशक, मुंबई संभाग ने दी। चीन में होने वाली प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर की चयन परीक्षा 25 से 30 अगस्त 2025 तक श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे-बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित की जाएगी। इस पृष्ठभूमि में, मुंबई डिवीजन के लिए चयन परीक्षा नेरुल जिमखाना में आयोजित की गई है। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के 15 वर्ष से कम आयु के पात्र लड़के-लड़कियाँ इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इस चयन में से संभाग के सर्वश्रेष्ठ पाँच लड़के और पाँच लड़कियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। मानदंड: खिलाड़ी का जन्म 1 जनवरी 2010 के बाद और 1 जनवरी 2014 से पहले होना चाहिए। मूल अंग्रेजी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, राष्ट्रीय परीक्षा के समय कम से कम छह महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट।

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से गायब हो जाएंगे आवारा कुत्ते!

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की भावनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से हो रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी संगठन या व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शीर्ष कोर्ट के इस फैसले पर पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने कहा, "यह आदेश 10 लाख जानवरों को प्रभावित करेगा, बहुत दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने, संहिताबद्ध कानून को रद्द कर रहा है। इस आदेश को चुनौती दी जाएगी। देश में मौजूदा शेल्टर सिर्फ एनजीओ और निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अचानक हटाने के परिणामों पर विचार भी नहीं किया। हमें दिल्ली को पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों का एक उदाहरण बनाना चाहिए था..."

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने दिया है। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह जनहित में यह कदम उठा रही है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की भावनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "हम यह अपने लिए नहीं, बल्कि जनता के हित के लिए कर रहे हैं। इसलिए, किसी भी तरह की भावनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि फिलहाल नियमों को भूलकर, सभी कुत्तों को इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में ले जाया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस विषय पर केवल केंद्र सरकार की दलीलें सुनी जाएंगी और किसी भी अन्य पक्ष, यहां तक कि पशु प्रेमियों की याचिका पर भी सुनवाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह इस आदेश को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नागरिक प्राधिकरणों, जिनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं, को तत्काल शेल्टर होम बनाने और कुत्तों को वहां ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन शेल्टर होम में पेशेवर लोग होने चाहिए जो कुत्तों को संभाल सकें, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर सकें। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी कुत्ता वहां से भाग न पाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी कुत्ते को गोद लेने की अनुमति नहीं होगी, ताकि अधिकारी शेल्टर होम में रखने के अपने काम को पूरा कर सकें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि दिल्ली में कुत्तों को रखने के लिए एक जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने उस पर रोक लगा दी थी। मेहता ने कोर्ट से कहा, "हम केवल कुछ पशु प्रेमियों के कारण अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते।"

साइबर अपराध पर अंकुश लगाने महाराष्ट्र के पास सबसे अच्छी प्रणाली और तकनीक

पेज 1 से आगे....

उन्होंने कहा कि भविष्य में इन उपकरणों का विस्तार और बेहतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धनराशि प्राप्त करने वाले लोगों को बधाई दी। पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंघल ने कार्यक्रम का परिचय कराया। उपायुक्त लोहित मतानी ने कार्यक्रम से पहले गरुड़ दृष्टि पर एक प्रस्तुति दी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने उपस्थित गणमान्यों का धन्यवाद किया। रोहित अग्रवाल 73 लाख रुपये, शशिकांत नारायण परांडे 34 लाख 77 हजार 724 रुपये, देवीदास पारखी 35 लाख 15 हजार 842 रुपये, विजय प्रकाश पाठक 19 लाख 90 हजार 354 रुपये, विजय मेंघानी 19 लाख रुपये, देवेन्द्र खराटे 12 लाख 81 हजार रुपये, श्रीमती।

राजमणि अजय जोशी के 29 लाख 95 हजार, राहुल चावड़ा के 15 लाख, बुद्धपाल बागड़े के 10 लाख, आदित्य गोयनका के 26 लाख 20 हजार 556, संगीता अष्टांकर के 8 लाख 24 हजार वापस किये गये.

सोशल मीडिया निगरानी : गरुड़ दृष्टि के लॉन्च होने के बाद से मीडिया पर 30,000 पोस्ट की जाँच की गई है।

आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई : इनमें से 650 आपत्तिजनक पोस्टों को नोट कर लिया गया है और उन्हें संबंधित प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है।

कानून एवं व्यवस्था नियंत्रण : इस उपकरण का उपयोग सोशल मीडिया से उत्पन्न अफवाहों, घृणास्पद भाषण और विवादास्पद पोस्ट से तनाव और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया है।

कम लागत वाला स्थानीय नवाचार : साइबर हैक 2025 प्रतियोगिता से उभरे इस उपकरण को बहुत कम लागत पर विकसित किया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार नागपुर पुलिस के पास हैं।

बहुमुखी क्षमताएं : गरुड़ दृष्टि न केवल अपराध की रोकथाम के लिए उपयोगी है, बल्कि सोशल मीडिया पर रुझानों का विश्लेषण करने, संदिग्ध खातों का पता लगाने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी उपयोगी है।

अमेरिका में एयरपोर्ट पर 2 विमान टकराए भीषण धमाके के बाद धधकी आग, उठा धुएं

अमेरिका – अमेरिका के मोंटाना स्थित कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर दो विमानों के बीच टक्कर हो गई जिससे भीषण आग लग गई। अमेरिका में दो विमानों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना अमेरिका के मोंटाना स्थित कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उतर रहा एक छोटा विमान, वहां खड़े एक विमान से टकरा गया। इस टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

चार लोगों को ले जा रहा सिंगल इंजन वाला छोटा विमान (सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप) दोपहर लगभग 2 बजे कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था। लैंडिंग के दौरान इस विमान ने एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

कि एक विमान आया, रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे विमान से टकरा गया। जो विमान उतरने का प्रयास कर रहा था उसमें आग लग गई, लेकिन पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकलने में सफल रहे। दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं और उनका एयरपोर्ट पर इलाज किया गया। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने दुर्घटना की आवाज सुनी और देखी। इलाके में काले धुएं का गुबार छाया हुआ था। पिछले हफ्ते ही अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ था। एक चिकित्सा परिवहन विमान उत्तरी एरिजोना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद विमान आग लग गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई थी। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क स्थित सीएसआई एविएशन कंपनी का यह विमान फ्लैगस्टाफ से लगभग 200 मील (321 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में चिनले हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में सवार लोग चिकित्साकर्मी थे जो एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहे थे।

पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, सेवाएं निलंबित

पेशावर – पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर विस्फोट कर रेलवे की पटरियों को उड़ा दिया गया है। विस्फोट की वजह से ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। इस ट्रेन को हाईजैक भी कर लिया गया था। पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। घटना पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले में हुई है। यहां पटरी पर लगे विस्फोटक के चलते जाफर एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जिस वक्त ट्रेन को निशाना बनाया गया उस वक्त वह पेशावर की ओर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी निशाना बनाया गया था और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था।

पाकिस्तान रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि क्वेटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्पेजैंड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ था। उन्होंने बताया कि धमाका तब हुआ था जब ट्रेन सुबह 9 बजे 350 यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर निकली थी। पाकिस्तान रेलवे के क्वेटा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुहम्मद काशिफ ने मीडिया को बताया, "रेल की पटरी पर लगे एक बम में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई।" अधिकारी ने बताया कि सभी घायल यात्रियों को मामूली चोटें आईं हैं। रेलवे कर्मचारियों सहित बचाव दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया है साथ ही फंसे हुए यात्रियों को क्वेटा पहुंचाने के लिए दुर्घटना राहत ट्रेन भी भेजी गई।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है जबकि पटरियां खाली कराने के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। इस बीच, एक अलग बयान में काशिफ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल की सेवाएं 14 अगस्त तक निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बोलन मेल 16 अगस्त (शनिवार) को अपना परिचालन फिर शुरू करेगी। निशाने पर है जाफर एक्सप्रेस क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में बार-बार निशाना बनाया गया है। सात अगस्त को बलूचिस्तान के सिबी रेलवे स्टेशन के पास रेलगाड़ी बाल-बाल बच गई थी, जहां पटरी के पास रखा गया बम रेलगाड़ी के गुजरने के तुरंत बाद फट गया था। एक अन्य घटना में चार अगस्त को कोलपुर के पास बंदूकधारियों ने इंजन को टारगेट करते हुए फायरिंग की थी। अलगाव वादी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जून में रेल पटरियों पर लगे एक रिमोट नियंत्रित विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया था, जिससे जैकोबाबाद में जाफर एक्सप्रेस के चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

न्यूज गैलरी

आदर्श सरकारी सौर जिला प्रतियोगिता आयोजित - सावे

मुंबई – गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्री अतुल सावे ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य में सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'मॉडल सरकारी सौर जिला' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गैर-परंपरागत ऊर्जा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने की पहल की है। जिस ज़िले में सरकारी भवनों का सौर ऊर्जाकरण सबसे तेज़ गति से होगा, उसे 'आदर्श सरकारी सौर ज़िला' घोषित किया जाएगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसमें भाग लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक पत्र प्रमाणित होकर संबंधित ज़िला कलेक्टर और महाप्रबंधक (महा ऊर्जा) को भेजना होगा। महाऊर्जा के माध्यम से पत्रों की जांच के बाद जिन जिलों में सबसे अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी, उन्हें आदर्श सरकारी जिला घोषित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रथम विजेता को 5 लाख रुपये, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये का होगा। ये पुरस्कार संबंधित जिला कलेक्टरों को सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल, 2026) पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा वितरित किए जाएँगे। मंत्री सावे ने सभी जिलों से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

'पहलवान खाशाबा जाधव पारंपरिक खेल महाकुंभ 2025'

मुंबई – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर की 300वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, महाराणा प्रताप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुर्ला क्रीड़ा संकुल में 'कुश्तीगीर खशाबा जाधव पारंपरिक खेल महाकुंभ 2025' का आयोजन किया गया है। पारंपरिक खेलों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आयोजित इस महाकुंभ का उद्घाटन बुधवार, 13 अगस्त को सुबह 11 बजे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा और पहलवान खशाबा जाधव के पुत्र रणजीत खशाबा जाधव विशेष रूप से उपस्थित थे। कौशल विकास विभाग और क्रीड़ा भारती द्वारा संयुक्त रूप से 13 से 22 अगस्त तक कुर्ला स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में कुल 16 प्रकार की पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी, जिनमें मल्लखम्ब, कबड्डी, खो-खो, भाला फेंक, विटी-दंडू, कुश्ती, लगोरी, लंगड़ी, रज्जू मल्लखम्ब और पारंपरिक दौड़ प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। पारंपरिक खेलों का संरक्षण और संवर्धन इन प्रतियोगिताओं की विशेषता है। पहलवान खशाबा जाधव पारंपरिक खेल महाकुंभ युवाओं में शारीरिक फिटनेस, टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। पिछले साल इस पहल में एक लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस साल भी राज्य के विभिन्न ज़िलों से खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और खिलाड़ियों को पारंपरिक खेलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

महाराष्ट्र चमड़ा, गैर-चमड़ा, जूते और सहायक उपकरण नीति 2025 के संबंध में हितधारक बैठक संपन्न हुई

मुंबई – महाराष्ट्र सरकार की चमड़ा, गैर-चमड़ा, फुटवियर और सहायक उपकरण नीति 2025 के मसौदे पर एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के कार्यकारी निदेशक आर. सेल्वम ने की। बैठक की शुरुआत में, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने राज्य में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इसकी खूबियों और प्रस्तावित नीति के प्रमुख स्तंभों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में टिकाऊ चमड़ा और फुटवियर निर्माण में वैश्विक अग्रणी बनने की क्षमता है।

परामर्श बैठक में उद्योग संघों, एमएसएमई, निर्यातकों, क्लस्टर प्रमुखों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। फुटवियर निर्माता कल्याण संघ और अन्य उत्पादक संगठनों ने भी भाग लिया। उद्योग क्षेत्र से प्रमुख अपेक्षाएं और सुझाव :

व्यापार में आसानी के लिए तीव्र अनुमोदन प्रक्रिया और सरलीकृत नियम। उच्च क्षमता वाले जिलों में सस्ती औद्योगिक भूमि की उपलब्धता। एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रमाणन और बाजार पहुंच के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि। शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) और वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुपालन को सुगम बनाने में सहायता करना। आधुनिकता के साथ-साथ पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने के लिए कोल्हापुर और सोलापुर जैसे पारंपरिक समूहों को सहायता। प्रोत्साहन योजनाओं को समय पर पारदर्शी तरीके से लागू करें।

अपेक्षित परिणाम – उद्योग जगत को उम्मीद है कि इस नीति से ब्रांडिंग, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। एनआईएफटी, एनआईडी, सीएलआरआई आदि संस्थानों के सहयोग से परीक्षण, अनुसंधान और डिज़ाइन केंद्र स्थापित करके डिज़ाइन और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल-आधारित प्रोत्साहन, श्रमिक कल्याण सुविधाएँ, सामाजिक सुरक्षा कवर से रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी। साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को भी बढ़ावा मिलेगा। एमआईडीसी के सीईओ पी. वेलारासु ने तैयार औद्योगिक भूखंडों, क्लस्टर विकास, बेहतर लॉजिस्टिक्स और त्वरित अनुमोदन पर ज़ोर दिया। उद्योग सचिव पी. अंबाल्गन ने हितधारकों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और 2030 तक 25,000 करोड़ के निवेश, 1 लाख रोज़गार और वैश्विक बाज़ारों में विस्तार के लक्ष्य को स्पष्ट किया। कार्यकारी निदेशक आर. सेल्वम ने पर्यावरण अनुकूल अनुसंधान सहयोग, निर्यात गुणवत्ता के लिए कौशल कार्यक्रम और उद्योग-सरकार संयुक्त प्रतिक्रिया प्रणाली पर जोर दिया।

सड़क हादसे में मृत पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर गांव ले गया पति

नागपुर – एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के पीछे शव को बांधकर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। पुलिस बाइक सवार शख्स का पीछा कर रही थी। वह बाइक अपनी नहीं रोक रहा था। बाइक के पीछे उसकी मृतक पत्नी का शव बंधा हुआ था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। नागपुर-जबलपुर मार्ग से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि एक बाइक सवार अपनी बाइक के पीछे एक महिला का शव बांधकर बड़ी तेजी से जा रहा है। यह घटना नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर हुई है। इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है, जो व्यक्ति अपनी बाइक पर महिला का शव लेकर जा रहा है, वह व्यक्ति उस मृत महिला का पति है। जानकारी के अनुसार, मृतक महिला का नाम ग्यारसी अमित यादव है, जबकि पति का नाम अमित यादव है। रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे देवलापार थाना क्षेत्र के मोर फाटा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से महिला का एक्सीडेंट हो गया था। पत्नी ट्रक के नीचे आ गई थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।

पीड़ित पति अमित यादव ने कहा कि नागपुर से लगभग 12:00 बजे वह अपने गांव रक्षाबंधन के लिए निकला था। देवलापार को जैसे उन्होंने पार किया बारिश होने लगी। सड़क पर पानी भरा हुआ था। एक ट्रक चालक ने कट मारा जिस वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक के साथ वो निचे गिर गया। तभी महिला ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। अमित बाइक के सामने जा गिरा। ट्रक चालक बाइक सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। जैसे-तैसे अमित यादव ने अपने को संभाला। उसके बाद वह मोबाइल और गाड़ी को उठाया। मृतक पत्नी को लेकर वह अपने गांव की तरफ चल दिया। अमित यादव ने बताया कि यह वीडियो पुलिस ने बनाया है। अमित यादव ने कहा कि वह काफी डरा हुआ था। अमित यादव अपनी पत्नी का शव बांधकर तेज रफ्तार से मध्य प्रदेश के करणपुर जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था, हाईवे पुलिस की उस पर नजर पड़ी, हाईवे पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। वह कुछ बताने को तैयार नहीं था। हाईवे पुलिस ने उसको रोक कर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे नागपुर भेज दिया। अमित और उसकी पत्नी पिछले 10 सालों से लोनारा नागपुर की कोराडी के पास रहते थे। रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश के करणपुर जा रहे थे। 15 साल पहले उनकी शादी हुई थी। 16 साल की एक बेटी भी है।

रेलवे बोगी कारखाने में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें

लातूर – रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लातूर जिले में रेलवे बोगी कारखाना स्थापित किया गया है। इस कारखाने में जल्द ही वंदे भारत रेलवे बोगियों का उत्पादन शुरू होगा, जिससे लगभग दस हज़ार रोज़गार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। वे सरकारी विश्राम गृह में आयोजित जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। पालक मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, विधायक विक्रम काले, विधायक संभाजी पाटिल निलंगेकर, विधायक संजय बनसोडे, विधायक अभिमन्यु पवार, विधायक रमेश कराड, पूर्व विधायक शिवाजी पाटिल कावेकर, पूर्व विधायक गोविंद केंद्र, विशेष पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप, जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर-घुगे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे और लातूर नगर आयुक्त श्रीमती। इस अवसर पर मानसी उपस्थित रहीं। महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती शहरी उत्थान महाभियान के तहत लातूर शहर की बढ़ी हुई जलापूर्ति योजना, जिला अस्पताल आदि का जायजा लिया गया. रेलवे बोगी कारखाने के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिले के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में आवश्यक ट्रेड शुरू किए जाने चाहिए और युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे साइट को विलासराव देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित करने के लिए रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक बैठक की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। उदगीर में सरकारी दूध पाउडर परियोजना को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। मदर डेयरी के सहयोग से इस परियोजना को फिर से सक्रिय करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस संबंध में एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा। जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए पुरानी सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

शौचालयों के लिए ठेका प्रणाली में बदलाव करें

मुंबई – मुंबई महानगर पालिका द्वारा शौचालयों के ठेके के लिए किया गया 30 साल का अनुबंध बहुत ही दमनकारी है और इसके कारण नागरिकों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन तथा मुंबई उपनगर के संयुक्त पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सुझाव दिया कि इस अनुबंध को रद्द कर नई प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।

मंत्री लोढ़ा ने इन समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लिया और नगर निगम के सहायक आयुक्त अरुण क्षीरसागर को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सायन-कोलीवाड़ा शौचालयों से संबंधित शिकायतें रखीं। नागरिकों ने बताया कि शौचालयों का तीस साल का अनुबंध होने के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है।

मंत्री लोढ़ा ने इस संबंध में मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी को एक पत्र भी लिखा है। महानगरपालिका के एफ उत्तर विभाग में आयोजित जनता दरबार में कई नागरिकों ने इस बारे में शिकायत की थी। उस समय विधायक प्रसाद लाड और कैप्टन तमिल सेलवन मौजूद थे।

जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार, मंत्री लोढ़ा नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए विभागवार जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के एफ उत्तर खंड में आयोजित जनता दरबार में नागरिकों ने निर्वाचन क्षेत्र के एफ/उत्तर खंड में आयोजित जनता दरबार में तीन सौ नागरिकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। नागरिकों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उन्हें एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संपर्क करने का अवसर मिला। मंत्री लोढ़ा ने नगर निगम अधिकारियों को गणेशोत्सव के दौरान सड़क मरम्मत, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति और साफ-सफाई के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक तमिल सेल्वन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता दरबार आयोजित करने के लिए मंत्री लोढ़ा का आभार व्यक्त किया।

सीपीसीबी ने खतरनाक तरल पदार्थों के सुरक्षित निकास और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में निपटान के उपायों को विनिदष्ट करते हुए एसओपी की जारी

नई दिल्ली – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। ये नियम उक्त नियमावली की अनुसूची-I में सूचीबद्ध 106 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों (ईईई) को विनियमित कर रहे हैं। इनमें छोड़े गए मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और यूपीएस प्रणालियां शामिल हैं।

एमओईएफ और सीसी ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किया है। यह नियम सभी प्रकार की बैटरियों अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट बैटरियों के एकत्रण और पुनर्चक्रण अथवा नवीनीकरण के लिए आयातकों सहित उत्पादकों को अनिवार्य रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य दिए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत ईपीआर ढाँचा लैंडफिल में अपशिष्ट बैटरियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने खतरनाक तरल पदार्थों के सुरक्षित निकास और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसके निपटान और उपयोग के पुनरुत्पादन के उपायों को विनिदष्ट करते हुए लेड एसिड बैटरी पुनर्चक्रण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के पंजीकरण, उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है ताकि उत्पादक के ईपीआर दायित्वों को पूरा किया जा सके। सीपीसीबी पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देशव्यापी बिक्री आंकड़ों और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत अनिवार्य अधिसूचित ईईई के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में उत्पन्न ई-कचरा नीचे दिया गया है: ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022, ई-कचरे को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से प्रबंधित करने और ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिये एक बेहतर ईपीआर व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करते हैं। इसमें सभी निर्माताओं, उत्पादकों, रिफर्बिशरों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यापार करने और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल तरीके से ई-कचरे के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में सुविधा प्रदान करते हैं और चैनलाइज करते हैं। ये नियम ईपीआर प्रणाली और ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नानुसार निम्नलिखित कदम उठाए हैं- सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई-कचरे के उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और रिफर्बिशर्स जैसी संस्थाओं को पंजीकृत करना आवश्यक है। सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देशों में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए अपेक्षित मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संदर्भ में प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना मौजूद है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्य योजना में एसपीसीबी/पीसीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वे अनौपचारिक ई-अपशिष्ट गतिविधियों की जांच के लिए नियमित अभियान चलाएं और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करें। पंजीकृत संस्थाएं ई-अपशिष्ट पोर्टल पर त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के माध्यम से अपना अनुपालन प्रस्तुत करती हैं। नियमों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी नामित एजेंसी द्वारा सत्यापन और लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि इन नियमों के अनुपालन की पुष्टि, आवश्यकतानुसार, रैंडम निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से की जा सके, ताकि इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, ताकि इन नियमों और इसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाई जा सके।

सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत अनौपचारिक ई-कचरा गतिविधियों की जाँच, ई-कचरे के अधिकृत विघटनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं के सत्यापन और व्यापक जागरूकता अभियान के संबंध में दिनांक 06.09.2022 के निर्देश।

अब केन्द्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध..... website : www.manvadhikar.com